(b) and (c). Question does not arise since no Marine National Park has been set up so for in the Andaman & Nicobar Islands.

Cases of Illegal Encroachment

6909. SHRI DIGVIJAY SINH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4516 on 22 March 1982 regarding achievement of National Forest Policy and state :

(a) how many illegal encroachments committed to the courts during the last two years have been compounded by payment of nominal fines from each State; and

(b) how many of such cases have actually resulted in eviction in each State :

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R.V. SWAMINATHAN): (a) and (b). Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

लगान की वसूली

6911. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओला वृष्टि, बाढ़ और सूखे के कारण फसल को 50 प्रतिशत से अधिक की हानि की स्थिति में लगान, तकाबी और बैंक ऋणों की वसूली रोक दी जाती है ;

(ख) क्या रोके गये ऋणों पर किसानों को अगले वर्ष दुगना ब्याज देना पड़ता है जिसके कारण उन पर अतिरिक्त भार पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेंगी कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिन ऋणों की वसूली रोकी जाये उन पर भविष्य में कोई ब्याज न लिया जाये ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदा के स्वरूप और उसकी सीमा को ध्यान में रखते हुए भू-राजस्व तथा तकाबी की वसूली के स्थगन के सम्बन्ध में निर्णय लेती हैं ।

जहां तक बैंकों का सम्बन्ध ऋणों का फिर से निर्धारित किया जाना है और इसकी वसूली लम्बी अवधि तक कर दी जाती है । सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋण लेने वालों की अदायगी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऋणों को फिर से निर्धारित करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ।

(ख) और (ग) जहां तक सहकारी ऋणों का सम्बन्ध है अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलने और दीर्घावधि ऋण की किस्तों को फिर से निर्धारित करने की सुविधायें उपलब्ध हैं । तथापि ऋण लेने वालों से यह आशा की जाती है कि वे देय ब्याज की अदायगी करें । छोटे और सीमान्त किसानों के मामले में जब उनके उत्पादन ऋण को मध्यावधि ऋण में तबदील किया जाता है, ब्याज की अदायगी पर जोर नहीं दिया जाता है ।

जहां तक वाणिज्यिक ऋणों का सम्बन्ध है, ब्याज की दरें भारतीय रिजर्व बैंक के